

| Date | Publication | Page no | Edition/Language |
|--------------------------------|-------------|---------|------------------|
| 30 th November 2019 | Samana | 08 | Mumbai/Marathi |

सामना

Headline: Pahle India Foundation makes crucial recommendations for policy reforms in 3 key industry sectors of Maharashtra

‘पहले इंडिया फाऊंडेशन’चे सर्वेक्षण

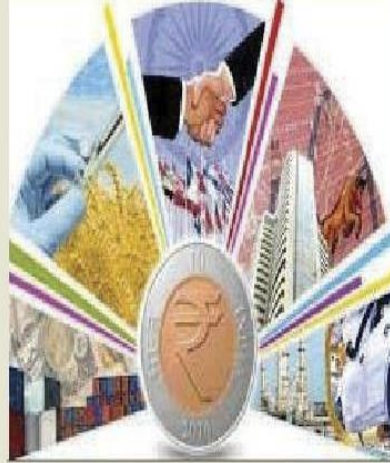
गेल्या दोन वर्षांत विकासदरात महाराष्ट्राचे स्थान घसरले

आठव्या स्थानावरून | साखर, अल्कोहोल उत्पादन, थेट १३ व्या स्थानी | पर्यटन उद्योगांत भारीची संधी

मुंबई, दि. २९ (प्रतिनिधी) - प्रगतशील महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षांत विकास दराच्या बाबतीत मोठी घसरण झाल्याचा निष्कर्ष ‘पहले इंडिया फाऊंडेशन’ या ‘एनजीओ’ने आपल्या सर्वेक्षणात काढला आहे. महाराष्ट्राला साखर, पर्यटन आणि अल्कोबेव्हेरेजेस (शीतपेये) उत्पादन क्षेत्रांत मोठी भारी घेण्याची संधी आहे, मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने अनेक प्रभावी उपाययोजना राबवायला हव्यात अशी सूचना ‘पहले इंडिया’ने आपल्या ‘ऑन इंटिग्रेटेड व्हॅल्यू चेन अप्रोच टू ईस ऑफ डुइंग बिझनेस : अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्कोबेव्ह अॅण्ड टुरिझम’ या सर्वेक्षण अहवालात केल्या आहेत.

■ २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या विकास दरात देशात आठवा क्रमांक होता. पण २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्याची १३ व्या स्थानावर घसरण झाली.

■ ही घसरण रोखून पुन्हा उन्नतीच्या दिशेने झेप घेण्यासाठी महाराष्ट्राला साखर उद्योग आणि पर्यटन उद्योगाचा मोठा उपयोग होऊ शकतो असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.



साखर उद्योग लाभदायक
महाराष्ट्रात २०१७-१८ मध्ये ७२,७३,७,००० टन साखरेचे तर ३,६३,००० टन मळीचे उत्पादन झाले आहे. ही मळी अल्कोहोल आधारित शीतपेये तयार करण्यासाठी वापरली जाते. म्हणजेच राज्याला साखर क्षेत्रातील ऊस उत्पादनातूनही मोठी आर्थिक कमाई होऊ शकते, असे पहले इंडियाच्या सहलेखिका व संशोधनप्रमुख निरूपमा सौंदरराजन यांनी म्हटले आहे.

पर्यटन क्षेत्रही विकासाला हात देऊ शकते

महाराष्ट्र पर्यटन क्षेत्राने वर्षभरात ११ टक्के पर्यटकवाढ करीत नवे रोजगार आणि उत्पन्न राज्याला मिळवून दिले आहे, मात्र त्यात अधिक प्रगती साधण्यासाठी राज्य सरकारने हॉटेल्स उभारणी मंजुरीसाठी एकखिडकी योजना राबवायला हवी असे आग्रही मत नॅशनल रेस्टॉरन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अनुराग कटियार यांनी व्यक्त केले.

| Date | Publication | Page no | Edition/Language |
|--------------------------------|-----------------|---------|------------------|
| 30 th November 2019 | Navbharat Times | 09 | Mumbai/Hindi |

FOUNDING TRUST • FOUNDING PAPER
NBT
 नवभारत टाइम्स

Headline: Pahle India Foundation makes crucial recommendations for policy reforms in 3 key industry sectors of Maharashtra

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वैल्यू चेन पर ध्यान दिया जाए’

बिजनेस डेस्क, मुंबई: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में महाराष्ट्र राज्य का नंबर जहां 2015-16 में 8 पर था, वह 2019 में 13वें नंबर पर आ गया। इसकी वजहें व उनके निदान के संबंध में पालिसी थिंक टैंक रहे पहले इंडिया फाउंडेशन (पीआईएफ) द्वारा बनाए गए ‘एन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन एप्रोच टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: अ केस स्टडी ऑफ



शुगर, अल्को-बेव टुरिज्म’ रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार के सामने रखी गई हैं। इस रिपोर्ट में

महाराष्ट्र के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र, चीनी, अल्को-बेव और पर्यटन क्षेत्र की विशिष्ट समस्याएं और उसके लिए आवश्यक सिफारिशें की गई हैं। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने उनकी नई सरकार द्वारा योजना पर विचार करने के लिए भी रखा गया है। पीआईएफ की निरूपमा सुंदरराजन ने कहा, ‘सभी क्षेत्र एक-दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण एक क्षेत्र की समस्या का दूसरे दो क्षेत्रों पर परिणाम होता है और पूरे वैल्यू चेन में समस्या निर्माण होती है। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में एक-दूसरे का एक दूसरे के साथ संबंध है। इसलिए सरकार इस पर भी ध्यान दे।’

| Date | Publication | Page no | Edition/Language |
|--------------------------------|------------------|---------|------------------|
| 30 th November 2019 | Janpath Samachar | 11 | Mumbai/Hindi |

जनपथ समाचार

Headline: Pahle India Foundation makes crucial recommendations for policy reforms in 3 key industry sectors of Maharashtra

पहले इंडिया फाउंडेशन की ओर से महाराष्ट्र के तीन महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रों में नीति सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें

मुंबई (संवाददाता)। महाराष्ट्र राज्य यह जीडीपी की दृष्टि से तथा आकार से सबसे बड़ा राज्य है, वित्तीय व्यवस्था पर सकारात्मक बदलाव लाने हेतु क्षेत्र के अनुसार मूल्य शृंखला के लिए अलग दृष्टिकोण की जरूरत है।

पॉलिसी थिंक-टैंक रहें, पहले इंडिया फाउंडेशन (पीआईएफ) द्वारा बनाए गए एन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन एप्रोच टू इज ऑफ बुईंग बिजनेस: अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्को-बेव एंड टुरिज्म इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र, चिनी, अल्को-बेव और पर्यटन क्षेत्र की विशिष्ट समस्याएं और उसके लिए आवश्यक सिफारिशें की गई हैं।

पीआईएफ द्वारा बनाए गए इस



पहले इंडिया फाउंडेशन की सीनियर फेलो एवं रिसर्च की प्रमुख सुश्री निरूपमा सुंदरराजन उद्योग क्षेत्रों में नीति सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में मीडिया को बताते हुए।

रिपोर्ट को राज्य सरकार के प्रतिनिधी पास 27 नवम्बर 2019 के दिन के पास तथा योजना कर्ताओं के सम्मन्न हुए एक गोलमेज सभा में

दिया गया। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे के सामने उनके नए सरकार द्वारा योजना पर विचार करने के लिए भी सामने रखा गया।


जीडीपी और आकार की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, 2014-15 में यह राज्य 8वें नम्बर पर था, इन आकड़ों में गिरावट आकर 2017-18 में यह राज्य 13वें स्थान पर खिसक गया है। पीआईएफ रिपोर्ट के अनुसार चिनी, अल्को-बेवरेजेस और पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ योजनात्मक सिफारिशें की गई हैं।

| Date | Publication | Page no | Edition/Language |
|--------------------------------|-----------------|---------|------------------|
| 30 th November 2019 | Hindmata Mirror | 14 | Mumbai/Hindi |

Headline: Pahle India Foundation makes crucial recommendations for policy reforms in 3 key industry sectors of Maharashtra

पहले इंडिया फाऊन्डेशन की ओर से महाराष्ट्र के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की योजनाओं में बदलाव करने हेतु की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें

यूटिलिटी डेस्क (एजेंसियां):
महाराष्ट्र राज्य यह जीडीपी की दृष्टि से तथा आकार से सबसे बड़ा राज्य है, वित्तीय व्यवस्था पर सकारात्मक बदलाव लाने हेतु क्षेत्र के अनुसार मूल्य शृंखला के लिए अलग दृष्टिकोन की जरूरत है. पालिसी थिंक टैंक रहें पहले इंडिया फाऊन्डेशन (पीआईएफ) द्वारा बनाए गए 'एन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन एप्रोच टू इज ऑफ डुईंग बिज़नेस: अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्को-बेव एन्ड टुरिज्म' इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई है. इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र, चिनी, अल्को-बेव और पर्यटन क्षेत्र की विशिष्ट समस्याएं और उसके लिए आवश्यक सिफारिशों की गई है. पीआईएफ द्वारा बनाए गए इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के प्रतिनिधि के पास तथा योजनाकर्ताओं के पास २७ नवम्बर २०१९ के दिन सम्पन्न हुए एक गोलमेज सभा में दिया गया. यह रिपोर्ट महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे के सामने उनके नए सरकार द्वारा योजना पर विचार करने के लिए भी सामने रखा गया. जीडीपी और आकार की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, २०१४-१५ में यह राज्य ८ वे नम्बर पर था, इन आकड़ों में गिरावट आकर २०१७-१८ में यह राज्य १३ वे स्थान पर खिसक गया है. पीआईएफ रिपोर्ट के अनुसार चिनी, अल्को-बेवरेजेस और पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ योजनात्मक शिफारिशों की गई है. यह एक एकात्मिक केस स्टडी है जो महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों को आय में बढ़ोत्तरी तथा रोजगार निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इन तीन क्षेत्रों का एकदुसरे के साथ सीधा संबंध है क्यों की चिनी क्षेत्र अल्कोबेव के लिए कच्चा माल का काम करता है उसका परिणाम



पर्यटन इस सेवा क्षेत्र पर होता है. यह सभी क्षेत्र एकदुसरे के साथ जुड़े होने के कारण एक क्षेत्र की समस्या का दुसरे दो क्षेत्रों पर परिणाम होता है और सम्पूर्ण मूल्यशृंखला में समस्या निर्माण होती है. इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में एकदुसरे का एक दुसरे के साथ संबंध है. इसलिए हम राज्य सरकार से यह बिनती करते हैं की ऐसे एकदुसरे के साथ संबंधित क्षेत्रों के मूल्यशृंखला का सरकार द्वारा अभ्यास करते हुए योजना बनायी जाए जिस स राज्य के जीडीपी पर सकारात्मक परिणाम हो सकें. इस रिपोर्ट की सह लेखकों में से एक और पहले इंडिया फाऊन्डेशन की सिनियर फेलो और रिसर्च की प्रमुख श्रीमती निरूपमा सुंदरराजन ने कहा.

महाराष्ट्र सरकार के नागरी उद्भयन, एक्साईज जीएडी की प्रमुख सचिव वत्सला नायर सिंग- आईएएस ने कहा इस रिपोर्ट के अधिकतर शिफारिशों को हमने देख लिया है तथा सरकार द्वारा गठीत की गयी कृती समिती द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोन रखकर बदलाव किए जाने पर ईओडीबी में महाराष्ट्र का क्रमांक सुधरने में सहयोग मिलेगा. हम अल्कोबेव क्षेत्र जैसे क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं तथा यह क्षेत्र देश की आर्थिक बातों के लिए महत्वपूर्ण है.

| Date | Publication | Page no | Edition/Language |
|--------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 30 th November 2019 | Dainik Shivner | 02 | Mumbai/Marathi |

दैनिक शिवनेर सर्वसामान्य जनतेचा बुलंद आवाज

Headline: Pahle India Foundation makes crucial recommendations for policy reforms in 3 key industry sectors of Maharashtra

पहले इंडिया फाऊन्डेशन तर्फे महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांच्या योजनांमध्ये बदल करण्यासाठी केल्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी

मुंबई, - महाराष्ट्र राज्य हे जी डी पी च्या दृष्टीने आकाराने सर्वात मोठे राज्य असून अर्थव्यवस्थेवर कोणताही सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी क्षेत्रानुसार मुख्य शुंखलेचा दृष्टिकोन वापरण्याची गरज आहे. पॉलिसी थिंक टँक पहिले इंडिया फाऊन्डेशन (पीआयएफ) द्वारे तयार करण्यात आलेल्या नॅटिग्रेटेड व्ह्यू चेन प्रॉच टू इश ऑफ डुईंग बिझनेस: अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्को-बेव्ज न्ह टुरिझम या रिपोर्ट मध्ये काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या रिपोर्ट मध्ये महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे म्हणजेच साखर, अल्कोबेव्ज आणि पर्यटन या क्षेत्रातील विशिष्ट समस्या आणि त्यासाठी आवश्यक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

पीआयएफ द्वारे तयार करण्यात आलेल्या रिपोर्ट ला राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींकडे आणि योजनाकार्यांकडे २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या एका गोमंज समेत सुपूर्द करण्यात आले. जी डी पी च्या आकाराच्या दृष्टीने पाहिल्यास महाराष्ट्र हे सर्वात मोठे राज्य असून ही २०१४-१५ मध्ये हे राज्य ८ वे होते, त्यावरून ही आकडेवारी सरळ २०१७-१८ मध्ये हे राज्य १३ वर आले आहे. या अहवाला द्वारे केलेल्या शिफारशी अमलात आणल्यास महाराष्ट्राची इस ऑफ डुईंग बिझनेस या श्रृंखलेत उभार सुधार होण्याची शक्यता आहे.

पीआयएफ रिपोर्ट मध्ये साखर, अल्को-बेव्ज रेजेस आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी काही योजनात्मक शिफारसी करण्यात आल्या असून हात एकलमिक केस स्टडी म्हणजे महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांतील महत्त्वपूर्ण महसूल आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या तीन क्षेत्रांचा एकमेकांशी सख्त संबंध आहे- कारण साखर क्षेत्र अल्कोबेव्ज साठी कच्चा माल तर पर्यटन हे क्षेत्र सेवा प्रदाता क्षेत्र आहे.

ही सर्व क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न असल्यामुळे एका क्षेत्रातील समस्येचा दुसऱ्या दोन क्षेत्रांवर परिणाम होतो व पूर्ण मुख्य श्रृंखलेत व्यवस्थ निर्माण होतो. अशाच प्रकारे अनेक क्षेत्रांमध्ये एकमेकांचा परस्पर संबंध आहेत. म्हणूनच आम्ही राज्य सरकारला अशी विनंती करतो की अशा एकमेकांचा संबंध असलेल्या क्षेत्रांच्या मुख्यश्रृंखलेचा सरकारने अभ्यास करून योजना तयार कराव्यात ज्यामुळे राज्याच्या जीडीपी वर चांगला परिणाम होऊ शकेल. असे या रिपोर्टच्या सह लेखिका वैकी एक आणि पहिले इंडिया फाऊन्डेशन च्या सिनियर फेलो आणि रिसर्च च्या प्रमुख व्. निरुपमा सौनंदरराजन यांनी सांगितले.

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील ऊसाचे उत्पादन हे २०१७-१८ मध्ये ३५५,०९८,००० टन इतके होते, म्हणजेच संपूर्ण देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या दोन तृतीयांश ही आकडेवारी आहे. २०१७-१८ मध्ये केवळ महाराष्ट्रालाच ७२,६३०,००० टन साखरेचे तर ३,६३,००० टन मळीचे उत्पादन झाले. साखर बाजारपेठ ही मळीच्या विक्रीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून थोड्या थोड्या कालावधीनंतर ही बाजारपेठ सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक पुरवठा सुरू ठेवावा लागतो. या उप-उत्पादनाचा लाभ वाढवणे हा सुध्दा या क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य पुनर्स्थापित करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.

साखर क्षेत्रातील सध्याच्या समस्या अधोखिल करताना वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी सांगितले साखर क्षेत्रात एक आरपी (फेअर न्ह रेग्युलेटिड प्रॉईस) सह अनेक आज्ञा असून यात अशी सूचना करण्यात आली आहे की शेतकऱ्यांना दिवसात पैस चायचे आहेत, तर साखरेचे उत्पादन झाल्यापासून विक्री



होण्याच्या या प्रक्रियेतला महिना लागतो. डॉ. सी रंगराजन समितीने दिलेल्या अहवालाची सुध्दा संपूर्ण अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आजूखी एक महत्त्वपूर्ण समस्या म्हणजे मळीपासून इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी अवकारी मंडुती मिळवणे, कारण हा इथेनॉल साठी लागणारा महत्त्वाचा कच्चा माल आहे.

साखर क्षेत्राशी निगडित असे अल्को बेव्ज क्षेत्र असल्याने महाराष्ट्र, यूपी आणि तमिस्र साखर उत्पादक क्षेत्रांना अधिक जोड उरपच मिळवण्याची मोठी संधी आहे. मागील सहा वर्षांच्या कालावधीत २०१३-१४ ते २०१८-१८ या कालावधीत महाराष्ट्रातील अवकारी करांचे उत्पन्न हे ७ टक्क्यांनी वाढले. यजेटच्या आकडेवारी नुसार अल्कोबेव्ज बाजारपेठ कडून एकूण अवकारी करानुत मिळणारा महसूल हा २०१८-१८ मध्ये १.४ लाख कोटी होता. २०१३-१८ आणि २०१८-१८ दरम्यान महाराष्ट्रातील करामध्ये सीएजीआर ७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले. २०१८-१९ मध्ये राज्याच्या अवकारी करानुत होणारे उत्पन्न हे रु १५३४३.१ कोटी इतके होते.

या क्षेत्रातील इस ऑफ डुईंग बिझनेस (ईओडीबी) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी या रिपोर्ट मध्ये १३ दीर्घकालावधीसाठी शिफारसी करण्यात आल्या असून अल्कोबेव्ज चे व्हन आणि उत्पादन करण्यासाठी ज्वळज्वळ ४४

परवानग्या आणि प्रक्रिया (किमान) पूर्ण कराव्या लागतात.

महाराष्ट्र सरकारच्या नागरी उद्यम, एक्सईजी जी ए डी च्या प्रमुख सचिव कल्या नायर सिंग आय ए एस यांच्या मते या रिपोर्ट मधील अधिकार शिफारसींची नोंद घेतली गेली असून सरकार द्वारे गठीत करण्यात आलेल्या कृती समितीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन हे बदल केव्हास ईओडीबी मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक सुधारण्यास मदत होईल. आम्ही अल्को बेव्ज क्षेत्रा सारख्या क्षेत्रात बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला असून हे क्षेत्र देशाच्या आर्थिक बाबींसाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. सर्व संबंधित क्षेत्रांची प्रगती करण्यासाठी व चांगले वातावरण निर्माण करण्यासाठी सातत्याने बदल करण्यात येतील.

पर्यटन हे सुध्दा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण महसूल देणारे क्षेत्र आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येत असतात- स्थानिक पर्यटकांच्या संख्येत वर्षाला टक्के सीएजीआर ने वाढ होत असून पर्यटकांची वाढ ही अनुक्रमे टक्क्यांनी होत आहे. हे क्षेत्र सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करते. या संदर्भात आदरातिथ्य, खाद्य आणि पेये

बाजारपेठा सुध्दा पर्यटनासाठी महत्त्वाच्या आहेत. एसआयसीई पर्यटन हे मोठ्या प्रमाणावर होतांना दिसते, म्हणूनच पीबीसीएल विभाग हा महसूल देणारा मोठा भाग आहे.

नॅशनल रेस्टुरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष श्री अनुराग कटियार यांनी सांगितले गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राने एकन्डबी बाजारपेठेसाठी सकारात्मक प्रगती केली आहे. आम्हाला आशा आहे की लवकरच रेस्टुरंट साठी आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया ही जरी बहुस्तरीय रचनेवरून एक खिडकी पध्दतीनुसार झाली नाही तरी किमान आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया सगळ्यात तरी व्हावी. यामुळे परवाने घेण्याचा कालावधी कमी होईल व व्यवसायाच्या एकूणच प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण अडथळा दूर होऊ शकेल.

या रिपोर्ट ने अशी सूचना दिली आहे की आदरातिथ्य बाजारपेठेसाठी एक विभाग/मंत्रालय देण्यात यावे. यामध्ये असेही सुचण्यात आले आहे की या क्षेत्रासाठी मध्यम आणि दीर्घकालावधीसाठी योजना करण्याची गरज आहे. अन्य महत्त्वपूर्ण शिफारसी मध्ये परवाने मिळवण्याचा कालावधी कमी करून विशिष्ट वेळेत देण्याची हमी देणे तसेच राज्याने सर्व परवान्यांसाठी एकसमान गरजा व नियम हे शाहे आणि जिल्ह्यांसाठी ठेवावेत.



| Date | Publication | Category |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| 26 th November 2019 | Financial Express | Online |

<https://www.financialexpress.com/economy/india-needs-sector-specific-measures-to-fight-economic-slowdown-heres-why-govt-should-change-approach/1774797/>



India needs sector-specific measures to fight economic slowdown; here's why govt should change approach

The Indian economy is an interplay of various sectors and secular growth can be ensured only by taking all the sectors upwards together and not in silos.

• Pawan Agarwal

The Indian economy is an interplay of various sectors and secular growth can be ensured only by taking all the sectors upwards together and not in silos. Ensuring a policy framework that will formulate measures to enhance the 'ease of doing business' on a sectoral basis can be a solution to arresting the economic slowdown.

On a year-to-date basis, the Sensex has gone up by 15% so far. But this has not been a linear one-sided growth for the Index. After having gone up from 34,981 in November 2018 to 40,267 in June 2019 the index slipped to 36,093 in September 2019 before closing at 40,360 as of this week. While this volatility creates a lot of discomfort among investors, especially the retail class, the bigger question to ask is what has prompted this kind of volatility in the markets and more importantly what is the solution to quelling it.

Last month, Amitabh Kant, chief of NitiAygog, unveiled an interesting report titled "An Integrated Value Chain Approach to Ease of Doing Business: A Case Study of Sugar, Alcohol Beverages, and Tourism Sectors". Put together by policy think-tank Pahle India Foundation, the report is interesting on many accounts.

| Date | Publication | Category |
|--------------------------------|-------------|----------|
| 30 th November 2019 | Arthniti | Online |

http://arthnitimagazine.blogspot.com/2019/11/blog-post_95.html?m=

अर्थनीती

पहले इंडिया फाऊन्डेशन तर्फे महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांच्या योजनांमध्ये बदल करण्यासाठी केल्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी

पहले इंडिया फाऊन्डेशन तर्फे महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांच्या योजनांमध्ये बदल करण्यासाठी केल्या महत्त्वपूर्ण शिफारसी

- क्षेत्रातील परस्परसंबंध आणि मुल्यभूखले वर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच बदलांच्या चौकटीचा वापर करून संपूर्ण व्यवसाय सोपा करण्यासाठी साखर, अल्को-बेव्हरजेस आणि पर्यटन या क्षेत्रांचा अभ्यास करून राज्याच्या जीडीपी मध्ये कशी वाढ होईल हे दर्शविण्यात आले
- पॉलिसी थिंक टँक तर्फे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रतिनिधींकडे रिपोर्ट ची प्रत सुपूर्द

मुंबई, २९ नोव्हेंबर २०१९- महाराष्ट्र राज्य हे जी डी पी च्या दृष्टीने आकाराने सर्वात मोठे राज्य असून अर्थव्यवस्थेवर कोणताही सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी क्षेत्रानुसार मुल्य भूखलेचा दृष्टिकोन वापरण्याची गरज आहे. पॉलिसी थिंक टँक पहले इंडिया फाऊन्डेशन (पीआयएफ) द्वारा तयार करण्यात आलेल्या 'अन इंटीग्रेटेड व्हॅल्यू चेन अप्रोच टू इझ ऑफ डुईंग बिजनेस: अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्को-बेव्हरजन्स' या रिपोर्ट मध्ये काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या रिपोर्ट मध्ये महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे म्हणजेच साखर, अल्कोबेव्ह आणि पर्यटन या क्षेत्रातील विशिष्ट समस्या आणि त्यासाठी आवश्यक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

पीआयएफ द्वारा तयार करण्यात आलेल्या रिपोर्ट ला राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींकडे आणि योजनाकर्त्यांकडे २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या एका गोलमेज संभेत सुपूर्द करण्यात आले. जी डी पी च्या आकाराच्या दृष्टीने पाहिल्यास महाराष्ट्र हे सर्वात मोठे राज्य असून ही २०१४-१५ मध्ये हे राज्य ८ वे होते, त्यावरून ही आकडेवारी घसरून २०१७-१८ मध्ये हे राज्य १३ वर आले आहे. या अहवाला द्वारे केलेल्या शिफारीशी अम्लात आणल्यास महाराष्ट्राची इस ऑफ डुईंग बिजनेस या श्रृंखलेत उत्तम सुधर होण्याची शक्यता आहे.

पीआयएफ रिपोर्ट मध्ये साखर, अल्को-बेव्हरजेस आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी काही योजनात्मक शिफारसी करण्यात आल्या असून हाह एकामिक केस स्टडी म्हणजे महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांतील महत्त्वपूर्ण महसूल आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या तीन क्षेत्रांचा एकमेकांशी सरळ संबंध आहे- कारण साखर क्षेत्र अल्कोबेव्ह सोठी कच्चा माल तर पर्यटन हे क्षेत्र सेवा प्रदाता क्षेत्र आहे.

“ ही सर्व क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न असल्यामुळे एका क्षेत्रातील समस्येचा दुसऱ्या दोन क्षेत्रावर परिणाम होतो व पूर्ण मुल्य श्रृंखलेत व्यत्यय निर्माण होतो. अशाच प्रकारे अनेक क्षेत्रांमध्ये एकमेकांचा परस्पर संबंध आहेत. म्हणूनच आम्ही राज्य सरकारला अशी विनंती करतो की अशा एकमेकांचा संबंध असलेल्या क्षेत्रांच्या मुल्यभूखलेचा सरकारने अभ्यास करून योजना तयार कराव्यात ज्यामुळे राज्याच्या जीडीपी वर चांगला परिणाम होऊ शकेल.” असे या रिपोर्टच्या सह लेखिका पैकी एक आणि पहले इंडिया फाऊन्डेशन च्या सिनियर फेलो आणि रिसर्च च्या प्रमुख कृ. निरुपमा सौनंदराजन यांनी सांगितले.

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील ऊसाचे उत्पादन हे २०१७-१८ मध्ये ३५५,०९८,००० टन इतके होते, म्हणजेच संपूर्ण देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या दोन तृतीयांश ही आकडेवारी आहे. २०१७-१८ मध्ये केवळ महाराष्ट्रातच ७२,६३७,००० टन साखरेचे तर ३,६३,००० टन मळीचे उत्पादन झाले. साखर बाजारपेठ ही मळीच्या विक्रीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून थोड्या थोड्या कालावधीनंतर ही बाजारपेठ सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक पुरवठा सुरू ठेवावा लागतो. या उप-उत्पादनाचा लाभ वाढवणे हा सुध्दा या क्षेत्राचे आर्थिक आरोग्य पुनर्स्थापित करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.

साखर क्षेत्रातील सध्याच्या समस्या अधोरेखित करतांना वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन चे कार्यकारी संचालक श्री. अजित चौगुले यांनी सांगितले “साखर क्षेत्रात एफआरपी (फेअर अँड रेम्युनेरेटिव्ह प्राईस) सह अनेक आव्हाने असून यांत अशी सूचना करण्यात आली आहे की शेतकऱ्यांना १४ दिवसात पेसे द्यायचे आहेत, तर साखरेचे उत्पादन झाल्यापासून विक्री होण्याच्या या प्रक्रियेला महिना लागतो. डॉ. सी रेगाराजुन समितीने दिलेल्या अहवालाची सुध्दा संपूर्ण अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. आणखी एक महत्त्वपूर्ण समस्या म्हणजे मळीपासून इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी अबकारी मंजूरी मिळवणे, कारण हा इथेनॉल साठी लागणारा महत्वाचा कच्चा माल आहे.”